ई-बसों के लिए नगर निगमों में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

- बसों की संचालन क्षमता बढ़ाने की कवायद में जुटा नगरीय परिवहन निदेशालय
- समीक्षा बैठक में निदेशक ने नगर निगम सीमा के अंदर ही बस चलाने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः ई-बसों के लिए 15 नगर निगमों में दो-दो अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम प्रशासन को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 15 नगरों में संचालित नगरीय परिवहन सेवाओं की शुक्रवार को हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक में नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन से बसों की संचालन क्षमता बढ़ जाएगी।

उन्होंने केवल नगर निगम सीमा के अंदर ही बसें चलाने के लिए कहा जिससे नगरवासियों को 15 मिनट के अंतराल पर बसें मिल सकें। निदेशक ने सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, मंडलायुक्त के नामित प्रतिनिधियों, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के पदाधिकारियों से कहा कि लखनऊ व कानपुर के नगर निगमों को छोड़कर बाकी जगह बसों को चार्जिंग के लिए डिपो ले जाना पड़ता है। यदि अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन बनेंगे तो बसों की संचालन क्षमता बढ़ जाएगी। ई-बस एक बार चार्जिंग में 120 से 125 किलोमीटर ही चलती हैं। लंबी दूरी तक चलने के कारण यदि उनकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाए तो बसों को बीच रास्ते में चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ही सरकार ने नगर निगमों में अवसर आधारित चार्जिंग स्टेशन (अपार्च्यूनिटी चार्जिंग स्टेशन) बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नगर निगम से जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

एक चार्जिंग स्टेशन के लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर और अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर जगह चाहिए। इससे बसों की संचालन क्षमता बढ़ जाएगी। निदेशक ने बैठक में कहा कि बसों के मार्गों पर उपयुक्त स्थानों का चयन कर जल्द से जल्द माडल बस स्टाप बनाएं जाएं। इसके लिए प्रत्येक नगर में आयुक्त की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों के दौरान जनता को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाए। अच्छे कार्य वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।